बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 220 ● नई दिल्ली ● वीरवार 18 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

अंजना ओम कश्यप को दिल्ली हाई से नहीं मिली राहत, खान सर मामले में वीडियो हटाने से कोर्ट ने फिर किया इंकार

नई दिल्ली। अपमानजनिक टिप्पणियां करने को लेकर फैसल खान (खान सर) सहित अन्य के खिलाफ टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप द्वारा दायर मानहानि मुकदमा पर बुधवार को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि पूर्व में जारी नोटिस पर कई प्रतिवादियों ने जवाब नहीं दाखिल किया है।

लोकसभा स्पीकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक से बोले- 19 जून को पार्टी में फूट मामले पर बताएं अपना पक्ष

नई दिल्ली । लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार, स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को 19 जून को मिलने के लिए कहा है। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य पार्टी में हुई फूट के मामले पर चर्चा करना है। स्पीकर चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखें और स्थिति स्पष्ट करें। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं

और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इससे पहले तृणमूल के असंतुष्ट धड़े ने 2023 में अस्तित्व में आई पूर्वोत्तर की राजनीतिक पार्टी- एनसीपीआई में विलय का एलान किया था। ये पार्टी त्रिपुरा का एक पंजीकृत गैर-मान्यप्राप्त दल है। इस पार्टी का गठन 2022 में हुआ था। शिवली कुंडू इसकी संस्थापक अध्यक्ष हैं। 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। दोनों ही उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। एनसीपीआई का

चुनाव चिन्ह पेन की नीब और सात किरणें हैं। दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे चार मई को आए थे।

इस चुनाव के बाद सत्ता गंवा चुकी पार्टी- तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में आंतरिक कलह जारी है। नतीजों की घोषणा के बाद से ही तृणमूल नेताओं में असंतोष देखा जा रहा है। आलम ये है कि पार्टी अब दो फाड़ होने की कगार पर है। संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और रायसभा) को मिलाकर कभी 40 सांसदों के साथ विपक्ष में दमदार भूमिका निभाने वाली टीएमसी अब अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। पार्टी के नेता मुखर होकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में हुई बड़ी बगावत ने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने अलग होकर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय का एलान कर दिया। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद हर कोई एनसीपीआई के बारे में जानना चाहता है। ये बागी लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के पहले भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल में पार्टी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से भी मिले। अब ये कहा जा रहा है कि जोड़ा फूल (टीएमसी का चुनाव चिह्न) और कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) की बात में पेन की सात किरणों (एनसीपीआई का चुनाव चिह्न) में 20 सांसदों वाली ऐसी चमक आई है जिसके चलते ये गुमनाम दल लोकसभा में पांचवां सबसे बड़ा दल बनने की स्थिति में पहुंच गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को प्रकाश चिक बराइक और कोयल मल्लिक ने रायसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बराइक और कोयल मल्लिक से पहले सुखेंदु शेखर रॉय और बंगाल से निर्वाचित महिला सांसद सुष्मिता देव ने भी सांसदी छोड़ दी है। सुखेंदु शेखर ने पद छोड़ने के बाद तृणमूल के कार्यकाल पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि उन्होंने आरजी कर अस्पताल में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद ही पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। दूसरी तरफ सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ने के बाद अपने गृह राय असम की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही।

स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, पोक्सो पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई; एलजी ने दिए निर्देश

नई दिल्ली । दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए राजधानी के सभी स्कूलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला किया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को लोकनिवास में हुई उच्चस्तरीय बैठक में पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के पालन की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों में कानून के अनुपालन की जांच करने के निर्देश दिए। बैठक में दिल्ली पुलिस के आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव और शिक्षा निदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एलजी ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षित वातावरण से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। बैठक में निर्देश दिया गया कि दिल्ली के प्रत्येक स्कूल में पोक्सो एक्ट के तहत तय नियमों और दिशा-निर्देशों की स्थिति का आकलन किया जाए। इसमें स्कूलों की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, जागरूकता कार्यक्रमों और शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। जिन संस्थानों में नियमों के पालन में कमी मिलेगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलजी ने दिल्ली पुलिस को स्कूल परिसरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। खासतौर पर स्कूलों की छुट्टी के समय और उन स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में छात्र आते-जाते हैं, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने को कहा गया है। इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और छात्रों व अभिभावकों में भरोसा कायम करना है। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ छेड़छाड़, उत्पीड़न और अन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर दिया गया। प्रशासन ने कहा कि राजधानी में ऐसा माहौल तैयार करना प्राथमिकता है, जहां हर बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करे और बिना किसी भय के शिक्षा प्राप्त कर सके। एलजी ने शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

'तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...', कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी

नई दिल्ली । भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कुछ वक्त पहले दिए गए कॉकरोच वाले बयान पर देशभर में खूब बवाल हुआ था. अब सीजेआई ने बुधवार (17 जून, 2026) को एक मामले की सुनवाई करते हुए फिर से एक ऐसा ही बयान दे दिया है. सीजेआई एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तुम लोग परजीवी हो, तुम्हारा जेल में रहना ही समाज के लिए बेहतर है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (17 जून, 2026) को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच साइबर अपराध से जुड़े एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान सीजेआई आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी परजीवी हैं, जो लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं और उन्हें पकड़ना भी मुश्किल होता है. ऐसे अपराधियों का जेल की सलाखों के पीछे रहना ही समाज के हित में है. देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई के दौरान साइबर अपराध के मामलों पर चिंता जताई और साथ-ही-साथ आरोपी को कड़ी फटकार भी लगाई. उन्होंने कहा, 'तुम लोग परजीवी हो, जो निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगते हो. साइबर अपराधियों के प्रति हमें बहुत सख्त होना ही पड़ेगा. तुम लोग किसी एक राय तक सीमित नहीं रहते. तमिलनाडु में किसी से फ्रॉड करते हो और फिर से वहां से जम्मू चले जाते हो. समाज का भला इसी में है कि तुम जैसे लोग जेल की सलाखों के भीतर ही बंद रहें.' इससे पहले सीजेआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी कर दी थी, जहां उन्होंने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी. इसके बाद उनके बयान को लेकर देशभर में खूब बवाल हुआ. यहां तक उनके बयान का हवाला देते सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक नई ऑनलाइन राजनीतिक पार्टी भी उभरकर सामने आ गई. उन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवा आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर सिस्टम पर ही हमला शुरू कर देते हैं. हालांकि, जब बवाल काफी यादा बढ़ गया तब सीजेआई ने अपने टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा था, 'मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है. मेरा बयान उन लोगों के लिए था, जो नकली और फर्जी डिग्री लेकर कानूनी पेशे में घुस जाते हैं.'

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली बीजेपी ने सफाई अभियानों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ मनाया जश्न

नई दिल्ली । दिल्ली बीजेपी नेताओं ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सफाई अभियानों और लोगों तक पहुंचने वाले कार्यक्रमों के ज़रिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और चल रही विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बोलते हुए दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ़ की और कहा कि भारत में आए बदलाव को इतिहास में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, हम सभी खुशनसीब हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल अपनी आँखों से देख रहे हैं। आने वाले सालों में, इतिहास की किताबों में यह दर्ज होगा और पढ़ाया जाएगा कि भारत का बदलाव और एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनने की उसकी यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के

कार्यकाल के दौरान शुरू हुई और तेज़ी पकड़ी। यह बात कि हम खुद इसे देख रहे हैं, बहुत गर्व की बात है... दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री का नारा है स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विकसित भारत 2047 की यात्रा सफ़ाई के रास्ते से होकर गुज़रती है। इस नज़रिए से, आज का सफ़ाई अभियान एक ऐसी दिल्ली की कल्पना करता है जो साफ़, सुंदर, पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण-मुक्त हो... इस बीच, दिल्ली भाजपाअध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा आयोजित सफ़ाई अभियान में हिस्सा लिया।

नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले राहुल गांधी की रैली, बीजेपी बोली- छात्रों को भटकाने की साजिश

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राजस्थान के कोटा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित इको ऑफ स्टूडेंट्स रैली की आलोचना की और उन पर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए व्यवधान पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा से कुछ दिन पहले यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गांधी की आलोचना की और कहा कि नीट परीक्षा तीन दिन बाद फिर से होने वाली है... जहाँ सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी संवेदनशीलता के बजाय चालाकी दिखा रहे हैं। त्रिवेदी ने सवाल करते हुए कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं- परीक्षा से ठीक पहले के 72 घंटों में, जब किसी उम्मीदवार को पूरी एकाग्रता के साथ अंतिम चरण की तैयारी करनी चाहिए, तब आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके छात्रों को मानसिक रूप से परेशान क्यों कर रहे हैं।

कांग्रेस का अमित शाह पर बड़ा हमला- लोकतंत्र बर्बाद कर रहे, एमपी तोड़ने में जुटे

नई दिल्ली । बुधवार को कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने और लालच देकर विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि बीजेपी उन नेताओं को निशाना बना रही है जो बीजेपी-विरोधी एजेंडे पर चुनाव जीतकर आए थे। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि इस साल की शुरुआत में संसद में मिली हार की भरपाई करने के लिए शाह विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके लुभावने प्रस्ताव उन लोगों को बीजेपी में शामिल होने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, जो सिर्फ़ दो साल पहले बीजेपी-विरोधी मज़बूत एजेंडे पर चुने गए थे। कहा जा रहा है कि उन्हें जो फ़ायदे दिए जा रहे हैं, वे हैरान करने वाले हैं। गृह मंत्री का ज़िक्र करते हुए रमेश ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री पूरी तरह से मतलबी अभियान चला रहे हैं, जो बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरह ही, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से कई तरह की स्कीम और प्रोडक्ट पेश करता है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बदनीयती की कोई सीमा नहीं है। लेकिन वे अपने असली मक़सद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना से नेताओं के पाला बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता का यह बयान आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मंगलवार देर रात आरोप लगाया कि राज्य के सांसदों को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं। ड्र पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अपना सपना मनी... मनी! ऐसी जानकारी है कि महाराष्ट्र के सांसदों को खरीदने के लिए आज रात 15 करोड़ रुपये की एडवांस रकम दी जाएगी। यह चौंकाने वाला और शर्मनाक है! ये दावे तब सामने आए जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में संभावित बगावत की खबरें तेज हो गईं; कहा जा रहा है कि कुछ लोकसभा सदस्य पार्टी से अलग होने पर विचार कर रहे हैं। राउत के दिल्ली दौरे के बाद भी सवाल उठे।

एनसीआर को दहलाने की साजिश- हिंदू नेता, खास जगह, हरियाणा के होटल, पाकिस्तान भेज रहे थे वीडियो

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की साजिश नाकाम करते हुए अंतरराष्ट्रीय आतंकी-आपराधिक मॉड्यूल का पर्दाफाश कर सात गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। इस मॉड्यूल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर से आतंकी बना शहजाद भट्टी और उसका सहयोगी अजमल गुजर चला रहा था। गिरफ्तार संदिग्धों में छह गाजियाबाद के हैं। इनमें लोनी निवासी अनस उर्फ अनस त्यागी (26), मोहित उर्फ योगी (26), साबिर (30), आरिफ उर्फ प्रधान (30), ट्रोनिका सिटी निवासी दीपक उर्फ दीपक एग्रोला (38), जतन (29) और पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का करनवीर सिंह (26) शामिल हैं। इन सभी का पुराना आपराधिक इतिहास है। इन पर हत्या, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, सभी पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से अवैध हथियार, गोला-बारूद और ड्रग्स यानी नशीले पदार्थों जैसे हेरोइन और चिट्टा की तस्करी कर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार संदिग्धों के कब्जे से पांच अत्याधुनिक सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल, 41 कारतूस, सात मोबाइल फोन, कई बैंक खातों का ब्योरा और सिंडिकेट की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली एक कार बरामद की है। मोबाइल फोन में भट्टी और गुजर से जुड़ी आपत्तिजनक चैट और वॉइस नोट शामिल हैं। पकड़े गए संदिग्धों में अनस, मोहित, दीपक, आरिफ, करनवीर सिंह पाकिस्तान में बैठे भट्टी और गुजर से सीधे संपर्क में थे। मोहित की तो गुजर से 1,000 से अधिक बार बातचीत हुई थी। साबिर सिंडिकेट का सक्रिय गुर्गा था और लॉजिस्टिक्स में मदद करता था।

पुलिस ने बताया, पिछले महीने खुफिया जानकारी मिली थी कि आईएसआई के इशारे पर भट्टी और गुजर सोशल मीडिया के जरिये भर्ती किए स्थानीय युवाओं के जरिये दिल्ली-एनसीआर में हमले की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तार आरोपियों से दिल्ली-एनसीआर के कई सार्वजनिक स्थानों, कुछ हिंदू नेताओं, प्रमुख हस्तियों और हरियाणा के प्रसिद्ध भोजनालय की रेकी कराई थी। संदिग्धों ने इन जगहों के वीडियो और तस्वीरें पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज भी दी थी।

पुलिस ने बताया कि संदिग्धों को उनके आकाओं ने दहशत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का निर्देश भी दिया था। पुलिस की जांच में पता चला कि भट्टी और उसके विदेश में बैठे साथी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कमजोर भारतीय युवाओं की पहचान करने, उन्हें भर्ती करने और उकसाने के लिए सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों का इस्तेमाल कर रहे थे। नेटवर्क युवाओं से संपर्क करने के लिए ऐसे माध्यमों का उपयोग करता था कि वे सुरक्षा एजेंसियों की नजर में न आ सकें। हवाला के जरिये पैसे पहुंचाए जाते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई समर्थित एक अंतरराष्ट्रीय आतंक-आपराधिक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली-एनसीआर के संवेदनशील स्थानों और कुछ हिंदू नेताओं की रेकी कर उनकी तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज रहे थे।

सम्पादकीय...

दावा या अधूरी हकीकत?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए प्रारंभिक समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया है। व्हाइट हाउस द्वारा रिपब्लिकन सांसदों और समर्थकों को भेजे गए आधिकारिक दस्तावेजों में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने उन समस्याओं का समाधान कर दिया है जिनसे अमेरिका पिछले चार दशकों से जूझ रहा था। इनमें ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर रोक, होर्मुज जलडमरूमध्य का पुनः खुलना और लेबनान में संघर्ष का अंत जैसे दावे शामिल हैं। लेकिन इन दावों और जमीनी हकीकत के बीच काफी अंतर दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जिस प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, उसके विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यहां तक कि अमेरिकी कांग्रेस के कई रिपब्लिकन सांसदों और इज़राइल जैसे करीबी सहयोगियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इस गोपनीयता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपब्लिकन सीनेटर शेली मूर कैपिटो ने भी स्वीकार किया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि समझौते में वास्तव में क्या शामिल है। उनका मानना है कि दस्तावेज अभी भी तैयार किया जा रहा है और प्रशासन तब तक इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता जब तक सभी पक्ष अंतिम रूप से सहमत न हो जाएं। ऐसी स्थिति में व्हाइट हाउस द्वारा पहले से ही बड़ी जीत का दावा करना कई विशेषज्ञों को जल्दबाजी लगता है। व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा दावा है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यह दावा सुनने में प्रभावशाली लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता अधिक जटिल है। ईरान दशकों से कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करना चाहता। हालांकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान के पास बड़ी मात्रा में 60 प्रतिशत तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक पहुंचना तकनीकी रूप से अपेक्षाकृत छोटा कदम है, जो हथियार-स्तर के यूरेनियम के लिए आवश्यक होता है। इसी कारण पश्चिमी देशों और इज़राइल को ईरान की मंशा पर संदेह बना हुआ है। यही वजह है कि केवल राजनीतिक घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भविष्य की परमाणु वार्ताओं में कौन-से निरीक्षण, नियंत्रण और सत्यापन तंत्र स्थापित किए जाते हैं। व्हाइट हाउस ने अपने दस्तावेज में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर के 2015 परमाणु समझौते की आलोचना भी की है। दावा किया गया है कि वह समझौता कभी औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं हुआ था। यह दावा आंशिक रूप से सही लेकिन भ्रामक है। वास्तव में समझौते से जुड़े विदेश मंत्रियों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे मंजूरी देकर अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान की थी। इसलिए यह कहना कि समझौता महत्वहीन था या औपचारिक नहीं था, पूरी तस्वीर को नहीं दर्शाता। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसी समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। अब उनका प्रशासन ईरान के साथ एक नए समझौते की दिशा में बढ़ रहा है, जिससे कई विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या नई व्यवस्था वास्तव में पुराने समझौते से बेहतर होगी। व्हाइट हाउस का दूसरा बड़ा दावा यह है कि होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल जाएगा और अमेरिकी परिवारों को पेट्रोल तथा रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में राहत मिलेगी। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन इसी मार्ग से होता है। लेकिन यह भी सच है कि युद्ध शुरू होने से पहले यह मार्ग सामान्य रूप से खुला हुआ था। संघर्ष के दौरान तेल आपूर्ति बाधित हुई और वैश्विक बाजारों में कीमतें बढ़ीं। इसलिए यदि समझौते के बाद जलडमरूमध्य फिर से सामान्य स्थिति में लौटता है, तो इसे नई उपलब्धि के बजाय युद्ध से पहले की स्थिति की बहाली कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि तेल बाजार और उपभोक्ता कीमतों को स्थिर होने में कई सप्ताह या महीनों का समय लग सकता है। व्हाइट हाउस ने यह भी दावा किया है कि ईरान को अमेरिकी करदाताओं का पैसा नहीं दिया जाएगा और केवल शर्तें पूरी होने पर आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही प्रशासन ने ओबामा काल के समझौते की आलोचना करते हुए कहा कि उससे ईरान को अरबों डॉलर मिले थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस समय ईरान को जो धनराशि मिली थी, वह उसके अपने जमे हुए विदेशी परिसंपत्तियों की वापसी थी, न कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे। इसी तरह जिन "नकदी से भरे पैलेट" का अक्सर राजनीतिक भाषणों में उल्लेख किया जाता है, उनका संबंध मुख्य रूप से एक पुराने हथियार सौदे और कैदियों की अदला-बदली से था, न कि सीधे परमाणु समझौते से। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि यह समझौता इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच संघर्ष को समाप्त कर देगा। लेकिन यह दावा सबसे अधिक विवादास्पद दिखाई देता है। हिज़्बुल्लाह इन वार्ताओं का हिस्सा नहीं है और उसने पहले ही ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार करने से इनकार किया है जिसमें उसकी भागीदारी न हो। दूसरी ओर इज़राइली अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि वे अमेरिका-ईरान समझौते के सभी प्रावधानों से बंधे नहीं होंगे। अमेरिका में इज़राइल के राजदूत येचिएल लीटर ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि लेबनान को इस समझौते में शामिल करना अनावश्यक और मददगार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इस मोर्चे पर अभी व्यापक सहमति नहीं बनी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ प्रारंभिक समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यदि यह समझौता वास्तव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करता है, क्षेत्रीय तनाव कम करता है और वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिरता प्रदान करता है, तो इसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल समझौते का पूरा पाठ सार्वजनिक नहीं है, प्रमुख पक्षों में कई सवाल बने हुए हैं और अनेक दावे अभी सत्यापित नहीं हुए हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि अमेरिका ने वास्तव में चार दशक पुरानी समस्या का समाधान कर लिया है। आने वाले दिनों में जब समझौते का विवरण सामने आएगा और कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय समुदाय तथा क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रियाएं स्पष्ट होंगी, तभी यह तय किया जा सकेगा कि यह समझौता वास्तव में शांति और स्थिरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है या फिर राजनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत की गई एक अधूरी कहानी।

नमो सिटी परियोजना - भीड़भाड़ से स्मार्ट और आत्मनिर्भर शहरों की ओर

भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के नए अवसरों और बेहतर जीवन सुविधाओं की मांग ने बड़े शहरों पर भारी दबाव पैदा कर दिया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जनसंख्या वृद्धि, यातायात जाम, प्रदूषण और आवास की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चार नई नमो सिटी विकसित करने की योजना एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी पहल के रूप में सामने आई है। यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो यह न केवल दिल्ली पर बढ़ते दबाव को कम करेगी, बल्कि उत्तर भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। नमो सिटी का विचार केवल नए शहर बसाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आधुनिक, स्मार्ट, पर्यावरण-अनुकूल और आत्मनिर्भर नगरों का निर्माण करना है। इन शहरों में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाएं, हरित ऊर्जा, बेहतर परिवहन व्यवस्था और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार का लक्ष्य ऐसे शहर विकसित करना है जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं और नागरिकों को उच्च गुणवत्ता का जीवन प्रदान करें। दिल्ली-एनसीआर आज देश का सबसे बड़ा शहरी समूह बन चुका है। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे शहरों में आबादी तेजी से बढ़ रही है। इससे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है। नई नमो सिटी परियोजना इस दबाव को कम करने का एक प्रभावी उपाय बन सकती है। जब लोगों को नए शहरों में बेहतर सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे तो राजधानी की ओर पलायन भी कम होगा। इन प्रस्तावित शहरों को सबसे बड़ी विशेषता उनका स्मार्ट सिटी मॉडल पर आधारित होना है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके यातायात प्रबंधन, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह योजना महत्वपूर्ण है। आज दिल्ली-एनसीआर विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है। नई नमो सिटी में हरित क्षेत्र, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा दक्ष भवनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि इन सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से पालन किया गया तो ये शहर सतत विकास के उत्कृष्ट उदाहरण बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह परियोजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। नए शहरों के निर्माण से निर्माण क्षेत्र, रियल एस्टेट, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण घरेलू और विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया जा सकेगा। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण की है। किसानों और स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करते हुए भूमि उपलब्ध कराना आसान कार्य नहीं होगा। इसके अलावा, परियोजना के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी। यदि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता नहीं रही तो लागत बढ़ सकती है और परियोजना में देरी भी हो सकती है। यह भी आवश्यक है कि इन नए शहरों का विकास केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन, जल प्रबंधन और सामाजिक सुविधाओं का समुचित विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। कई बार देखा गया है कि नई टाउनशिप तो विकसित हो जाती हैं, लेकिन वहां रोजगार और आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण लोग बसने में रुचि नहीं लेते। इसलिए नमो सिटी को वास्तव में आत्मनिर्भर और जीवंत शहर बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। अंधाधुंध निर्माण कार्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा सकता है। इसलिए हरित क्षेत्र, जल स्रोतों और जैव विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, स्थानीय समुदायों को योजना निर्माण और क्रियान्वयन प्रक्रिया में शामिल करना भी आवश्यक है ताकि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंच सके। नमो सिटी परियोजना केवल एक शहरी विकास योजना नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के शहरों की परिकल्पना है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को भी मजबूत करती है, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा, तकनीकी नवाचार और सतत विकास को विशेष महत्व दिया गया है। यदि यह योजना समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू होती है तो यह देश के अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। निष्कर्ष- दिल्ली-एनसीआर में चार नई नमो सिटी विकसित करने की योजना भारत के शहरी विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यह न केवल राजधानी क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को कम करेगी, बल्कि रोजगार, निवेश और। आधुनिक- जीवन सुविधाओं के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी। हालांकि सफलता के लिए पारदर्शी कार्यप्रणाली, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों की भागीदारी और दीर्घकालिक योजना अत्यंत आवश्यक होगी। यदि इन पहलुओं पर गंभीरता से काम किया गया, तो नमो सिटी वास्तव में आधुनिक, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की पहचान बन सकती हैं।

रानी लक्ष्मीबाई...

काशी में जन्मी, बिठूर में पली बढ़ी, झांसी में रानी का पद प्राप्त करने वाली लक्ष्मी बाई का जीवन संघर्षों की कहानी है। सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों से टक्कर लेने वाली और ग्वालियर में अंग्रेज़ों से ही युद्ध करते हुये प्राणोत्सर्ग करने वाली वीरांगना लक्ष्मी बाई का साहस और व्यक्तित्व उनके हर कार्य में छलकता था। सन् 1853 ई. में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर रानी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक ओर सदाशिव राव भाऊ अपने को झांसी की गद्दी का असली उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे थे, तो दूसरी ओर पड़ोसी राज्य ओरछा की लड़ाई में सरकार झांसी राज्य हड़पने की योजना बना रही थी, ऊपर से अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि भी झांसी पर लगी हुई थी। रानी लक्ष्मी बाई तीनों ओर से घिरी हुई थी। अंग्रेजों ने राजा रानी द्वारा गोद लिये - बालक दामोदर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। झांसी की सेना अव्यवस्थित थी, युद्ध का सामान नहीं था। रानी के चारों ओर भयावह स्थिति थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में लक्ष्मी बाई ने बड़े धैर्य और साहस से कार्य किया। उन्होंने अपने चारों ओर मंडराते हुये युद्ध के बादलों को छितराने के लिये युद्ध सामग्री को एकत्रित किया। पहली बार रानी लक्ष्मी बाई ने स्त्रियों को युद्ध की शिक्षा देकर उनका अलग से सैन्य दल बनाया। सेना सुव्यवस्थित होते ही रानी ने सदाशिवराव पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। ओरछा राज्य के सेनापति को युद्ध के मैदान से भगाया। वह अंग्रेज़ों से जा मिला किंतु रानी ने इसकी चिंता नहीं की। अंग्रेज़ों की दृष्टि पहले से ही झांसी पर लगी हुई थी। जब अंग्रेजों ने अपने मित्र राज्य ओरछा की सेना की पराजय सुनी तो वे चौकन्ने हो गये। यह ऐसा था जब देश में अंग्रेज़ों के विरोध में आग सुलग रही थी। बिठूर में नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे अतः उद्देश्य एक था, अतः दोनों ही एक दूसरे की मुसीबत के समय सहायता को हमेशा तत्पर थे। रानी ने मर्दन सिंह को लिखे एक पत्र में लिखा था कि- विदेशियों का शासन भारत वर्ष में नहीं होना चाहिये। मर्दन सिंह ने भी रानी के विचारानुरूप उनका तब तक साथ दिया जब तक कि वे जेल के सींखचों के बाहर रहे। ह्यूरोज की सेना के आगे मर्दनसिंह टिक नहीं सके। वे भागकर नरसिंहगढ़ चले गये। ह्यूरोज़ ने वहाँ भी आक्रमण कर दिया। मर्दनसिंह को वहाँ से भी भागना पड़ा। ह्यूरोज विद्रोहियों कोटे हराता हुआ सागर पहुँचा। सागर से उसने झांसी के लिये कूच किया। रास्ते में उसने मर्दनसिंह और बखतवली को हराते हुये बानपुर पर भीषण आक्रमण किया। वहाँ से झाँसी की ओर बढ़ा। जनरल गेर के साथ ह्यूरोज़ अपनी सशस्त्र सेना के साथ झाँसी पहुँचा। झाँसी के किले को उसने चारों ओर से घेर लिया। ऐसी विषम स्थिति में रानी ने तात्या टोपे को सहायता के लिये पत्र लिखा। इस समय तक मर्दनसिंह और बखतवली भागकर कालपी गये थे। झाँसी की ओर प्रस्थान करने के लिये तात्या टोपे नाना साहब से अनुमति प्राप्त कर बाईस हजार सैनिकों के साथ झाँसी की ओर बढ़े, किंतु वह कुछ समय के लिये चरखारी में उलझ गये। वहाँ से चलकर तात्या टोपे ने मऊ में मुकाम किया। यहाँ से उसने झाँसी की स्थिति का पता लगाकर युद्ध की घोषणा की। किंतु यह सेना झाँसी तक नहीं पहुँच पाई। ह्यूरोज की सेना ने तात्या टोपे की सेना को झाँसी के बाहर ही हटा दिया। अंग्रेज़ी सेना ने झाँसी के किले में बार बार आक्रमण कर झाँसी पर कब्जा कर लिया। रानी को झाँसी को छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। ह्यूरोज़ को झाँसी पर कब्जा करने के लिये वीरांगना लक्ष्मी बाई के साथ कठिन संघर्ष करना पड़ा था।

कीव की पवित्र धरोहर पर हमला- युद्ध, संस्कृति और इतिहास के बीच फंसा यूक्रेन

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध केवल सैन्य संघर्ष तक सीमित नहीं रह गया है। यह लड़ाई अब इतिहास, संस्कृति, धर्म और राष्ट्रीय पहचान के प्रश्नों को भी अपने भीतर समेट चुकी है। हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के केंद्र कीव-पेचेर्स्क लावरा पर हुए हमले ने इस संघर्ष को एक नया आयाम दे दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे ईसाई सभ्यता और विश्व सांस्कृतिक विरासत पर हमला बताया है, जबकि रूस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह क्षति यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली की विफलता के कारण हुई। हमले में कीव और खार्किव सहित कई शहरों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के अनुसार रूस ने एक ही रात में 70 से अधिक मिसाइलें और 600 से अधिक ड्रोन दागे। इन हमलों में कम से कम दस लोगों की मौत हुई और कई महत्त्वपूर्ण इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। लेकिन सबसे अधिक ध्यान कीव-पेचेर्स्क लावरा को पहुंचे नुकसान ने आकर्षित किया, जिसे यूक्रेन और विश्वभर के ईसाइयों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है।

क्या है कीव-पेचेर्स्क लावरा?

कीव-पेचेर्स्क लावरा, जिसे मठ ऑफ द केव्स भी कहा जाता है, लगभग एक हजार वर्ष पुराना धार्मिक परिसर है। यह यूक्रेन की सबसे महत्वपूर्ण ईसाई धरोहरों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसकी गुफाओं में अनेक संतों के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं, जिसके कारण यह पूर्वी यूरोप के प्रमुख तीर्थस्थलों में गिना जाता है। यह स्थल केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रूस और यूक्रेन दोनों की ऐतिहासिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास प्राचीन रूस या कीवन रस से जुड़ता है, जिसे आधुनिक रूस, यूक्रेन और बेलारूस की साझा सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। इसी कारण यह स्थान दोनों देशों की ऐतिहासिक स्मृति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गया है। रूसी राष्ट्रपति लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि रूस और यूक्रेन एक ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समुदाय के हिस्से हैं। उन्होंने कई बार कीवन रस की विरासत का उल्लेख करते हुए यूक्रेन पर रूस के प्रभाव को उचित ठहराने की कोशिश की है। दूसरी ओर यूक्रेन इस विरासत को अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान का आधार मानता है। यही कारण है कि कीव-पेचेर्स्क लावरा जैसे स्थलों पर हमला केवल एक सैन्य घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे यूक्रेन की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान पर आघात के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस घटना को ईसाई संस्कृति के विरुद्ध सबसे बड़े अपराधों में से एक बताया। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यह स्थल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ईसाई पवित्र स्थलों में से एक है। हमले के बाद रूस ने साफ तौर पर कहा कि उसने जानबूझकर इस धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया। रूसी अधिकारियों का दावा है कि यूक्रेन की अमेरिकी निर्मित पैट्रियट मिसाइल प्रणाली में खराबी आने के कारण यह क्षति हुई। इसके विपरीत यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि घटनास्थल से रूसी ड्रोन के अवशेष मिले हैं, जो यह संकेत देते हैं कि हमला सीधे रूसी हमले का परिणाम था। युद्ध के दौरान इस तरह के दावों और प्रतिदावों की सत्यता स्वतंत्र रूप से जांचना अक्सर कठिन होता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच की मांग कर रहा है इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यूक्रेन और रूस के बीच धार्मिक विभाजन है। वर्षों तक यूक्रेनी ऑर्थोडॉक्स चर्च का संबंध मॉस्को पैट्रिआर्केट से रहा। लेकिन 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेनी चर्च ने स्वयं को रूसी धार्मिक नेतृत्व से अलग कर लिया। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख खुले तौर पर रूस की सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर चुके हैं। दूसरी ओर ने यूक्रेन के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया है। इस कारण धार्मिक संस्थाएं भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गई हैं। यूक्रेन ने इस हमले की तुलना उन घटनाओं से की है जब आतंकवादी संगठन ने मध्य पूर्व में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया था। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने के मामले में आईएसआईएस से भी आगे निकल गया है। यूनेस्को के अनुसार कीव-पेचेर्स्क लावरा मानव रचनात्मक प्रतिभा का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी वास्तुकला, कला और धार्मिक महत्व इसे विश्व की अमूल्य धरोहरों में स्थान दिलाते हैं। ऐसे में इस स्थल को हुआ नुकसान केवल यूक्रेन का नुकसान नहीं बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक विरासत की क्षति माना जा रहा है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि यह वैसा ही है जैसे फ्रांस में या पर बमबारी कर दी जाए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भी इसे सार्वभौमिक विरासत पर हमला बताया। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख ने नागरिक ठिकानों पर रूसी हमलों को युद्ध अपराध करार दिया है और रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वहीं यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि यूनेस्को और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देंगी। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों और हथियारों के बीच नहीं लड़ा जाता। इसके प्रभाव समाज, संस्कृति, धर्म और इतिहास तक पहुंचते हैं। जब किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक धरोहर पर हमला होता है तो वह केवल इमारतों का नुकसान नहीं होता, बल्कि सामूहिक स्मृति और पहचान पर भी चोट होती है। कीव-पेचेर्स्क लावरा पर हुआ हमला रूस-यूक्रेन युद्ध के सबसे संवेदनशील अध्यायों में से एक बन सकता है। चाहे यह हमला जानबूझकर किया गया हो या दुर्घटनावश हुआ हो, इसका प्रभाव राजनीतिक सीमाओं से कहीं आगे तक जाएगा। यह घटना याद दिलाती है कि युद्ध की आग केवल वर्तमान को नहीं जलाती, बल्कि इतिहास और विरासत को भी अपनी चपेट में ले लेती है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष में यह हमला सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा, धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक स्मृतियों के संरक्षण को लेकर नए प्रश्न खड़े करता है। आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय जांच और कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं यह तय करेंगी कि इस घटना को इतिहास किस रूप में याद रखेगा–एक युद्ध दुर्घटना के रूप में या सांस्कृतिक विरासत पर गंभीर हमले के रूप में।

राहुल को प्रतिरोध का नारा बनाएगा विपक्ष का चेहरा, 2029 में पीएम मोदी और नेता विपक्ष का सीधा मुकाबला

लोकसभा चुनाव में अभी तीन साल का वक्त है लेकिन राजनीति जिस दिशा में चल पड़ी है, उससे साफ जाहिर है कि न सिर्फ 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव बल्कि अब 2029 तक जितने भी चुनाव होंगे सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच ही सीधा मुकाबला होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस राहुल गांधी को अपने नेता और भावी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ेगी और इससे सहमति असहमति सहयोगी दलों पर छोड़ देगी। उधर स्वाभाविक रूप से एनडीए और भाजपा का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे।

युवाओं और छात्रों से सीधे संवाद की पहल का मकसद क्या?

इसका संकेत खुद राहुल गांधी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में दिए गए अपने भाषण में दिया। उन्होंने कहा कि अब देश में चुनावों की परंपरागत राजनीति से आगे प्रतिरोध की राजनीति का युग आ गया है। प्रतिरोध की राजनीति से राहुल गांधी का सीधा मतलब है कि मोदी सरकार को संसद के साथ-साथ विपक्ष अब सड़क पर भी घेरेगा। राहुल ने कहा कि सभी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हैं और चुनावों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए कांग्रेस को प्रतिरोध की राजनीति के अपने पुराने दौर में लौटना होगा। राहुल ने सिर्फ एलान ही नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रतिरोध की राजनीति की शुरुआत करते हुए सबसे पहले युवाओं और छात्रों से सीधे संवाद करने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है जिसकी शुरुआत वह कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में छात्र युवा सम्मेलन से कर रहे हैं। भाजपा और एनडीए तो 2014 से ही चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी को आगे करके उनके नाम पर ही हर चुनाव लड़ रहा है। सत्ता पक्ष के लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और नाम चुनावों में जीत का सबसे बड़ा मंत्र है जबकि इसके विपरीत कांग्रेस मोदी के मुकाबले अपने किसी भी नेता को आगे करके चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी इंडिया गठबंधन भी मोदी के मुकाबले बिना कोई चेहरा आगे लाए ही मैदान में उतरा था। लेकिन अब कांग्रेस जिस राह पर चल पड़ी है, उससे यह साफ है कि अब उसे नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को आगे करने में कोई गुरेज नहीं है। अब राहुल गांधी खुद आगे बढ़कर सरकार के खिलाफ होने वाली लड़ाई की कमान संसद के साथ सड़क पर भी संभालने के लिए तैयार हैं।

भाजपा ने क्यों नहीं गिना नेहरू के 1946 से लेकर 1952 तक का कार्यकाल?

हाल ही में भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारह साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस जश्न के दौरान न सिर्फ मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जोर-शोर से प्रचार प्रसार किया गया बल्कि यह भी बताया गया आम चुनावों से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। इसे साबित करने के लिए नेहरू के 1946 से लेकर 1952 तक के कार्यकाल को इस आधार पर छोड़ दिया गया कि यह समय देश के पहले आम चुनावों से पहले का था। इसलिए 1952 के आम चुनावों के बाद से नेहरू के कार्यकाल की तुलना मोदी के 2014 से अब तक के कार्यकाल से की गई और बताया गया कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए।

क्या आगे भी सारे चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ेगा एनडीए?

हालांकि नेहरू पहले 1946 में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मनोनीत हुए। इसके बाद जब देश 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो संविधान सभा निर्वाचित हुई और नेहरू फिर प्रधानमंत्री बने और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भी संविधान सभा भंग नहीं हुई बल्कि संसद के रूप में 1952 में चुनावों के बाद नई सरकार के गठन होने तक बनी रही। इसलिए नेहरू के इस कार्यकाल को अनिर्वाचित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष की यह कवायद 2029 के लोकसभा और उससे पहले होने वाले चुनावों के लिए फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे को ज्यादा चमकदार और कामयाब बनाकर जनता के बीच पेश करने के लिए की जा रही है। यानी यह तय है कि आगे भी सारे चुनाव एनडीए मोदी के चेहरे और नाम के सहारे ही लड़ेगा। उधर विपक्षी खेमे की तस्वीर अब खासी बदल गई है।

हाल ही में हुए पांच विधानसभा चुनावों में प.बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन के किले ढह गए और इसके पहले बिहार में तेजस्वी यादव, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भाजपा के हाथों हार चुके हैं। कांग्रेस भी 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और असम में भाजपा से हारी है लेकिन केरल में उसकी जीत और तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर टीवीके सरकार में शामिल होने से पार्टी को फिर आक्सीजन मिल गई है। इसलिए अब मामला कांग्रेस और क्षत्रपों के बीच बराबरी का हो गया है और अब कोई भी क्षत्रप कांग्रेस को यह उलाहना नहीं दे सकता कि भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय दल ही सफलता पूर्वक कर पाते हैं।

2029 के लोकसभा चुनावों से पहले राज्यों के सियासी समीकरण कैसे?

क्षत्रपों में अब झारखंड में हेमंत सोरेन अकेले ऐसे नेता हैं जो दो बार लगातार भाजपा को चुनावी मात दे चुके हैं और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है जबकि 2014, 2017, 2019 और 2022 में लगातार भाजपा के हाथों चुनावी हार झेल चुके अखिलेश यादव ने 2024 में लोकसभा चुनावों में भाजपा को पटखनी देकर फिर से 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए खम ठोंक रहे हैं। अब 2027 में उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, जहां चुनाव में भाजपा का सपा से मुकाबला होगा और कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी होगी। वहीं पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा क्योंकि वहां भाजपा अभी अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है और अकाली दल के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। बाकी 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले सारे राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होगा। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां भी कांग्रेस मुख्य किरदार होगी।

विदेश से जुड़े मुद्दों पर क्या है विपक्ष का रुख?

इसलिए अब ज्यादातर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सामने कहीं अपनी सरकारें बचाकर दोबारा जीतने की और कहीं भाजपा को हराने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश जहां कांग्रेस सपा की सहयोगी पार्टी होगी वहां भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी बहुत कुछ नतीजे निर्भर करेंगे। यह बात कांग्रेस नेतृत्व समझ रहा है और इसीलिए अब बिना देर किए राहुल गांधी ने खुद को मैदान में उतार दिया है। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पर्चा लीक हो, सीबीएसई का गड़बड़झाला हो, भारत अमेरिका व्यापार समझौता हो, खाड़ी युद्ध में भारत की विदेश नीति हो और अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा हो हर मुद्दे पर राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही घेर रहे हैं। इस तरह उन्होंने एक तरह से मोदी के सामने खुद को सबसे बड़ी विपक्षी चुनौती के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। सत्ता पक्ष इसे समझ चुका है इसलिए उसके भी हमले सबसे ज्यादा राहुल गांधी पर ही हो रहे हैं। इससे जाने अनजाने सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी को ही मोदी के सामने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बना रहा है।

राहुल के प्रतिरोध के एजेंडे पर चर्चा क्यों?

अब सवाल है कि क्या क्षेत्रीय दल जो भले ही इन दिनों अस्त-व्यस्त हैं कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। कांग्रेस की रणनीति है कि उसे अपने संघर्ष के कार्यक्रम पर आगे बढ़ना है।राहुल गांधी ने लगभग उसी तरह पूरे विपक्ष और खुद कांग्रेस के सामने प्रतिरोध की राजनीति की चुनौती पेश कर दी है, जैसे कभी महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के दौरान उस कांग्रेस के सामने खड़ी की थी जो लंबे समय तक अंग्रेजों को सिर्फ ज्ञापन देने और उससे चर्चा करने का क्लब भर थी।गांधी ने उसे सीधे अंग्रेज सरकार से सत्याग्रह के जरिए प्रतिरोध की राजनीति के अगुआ संगठन में बदल दिया था।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार पाठी ने बन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पोर्टलबाड़ा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार पाठी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08862)

श्रमिक सुविधा केंद्र एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

दुदही, कुशीनगर।

विकास खण्ड दुदही के ग्राम पंचायत गौरी श्रीराम स्थित पंचायत भवन में एक्शन एड एसोसिएशन, श्रमिक सुविधा केंद्र तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता एवं सामाजिक सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, कानूनी अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामवृक्ष गिरि ने श्रमिकों के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने पेंशन, आवास, राशन कार्ड तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण और उससे मिलने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायमित्र पवन कुमार एवं एनुल्लह अंसारी ने प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, स्थायी लोक अदालत, जागृति योजना, जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में उपस्थित लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद नागरिक निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। श्रमिक सुविधा केंद्र की प्रतिनिधि दुर्गा देवी ने केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और श्रमिक हित में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। शिविर के दौरान 15 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया, जबकि विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित सैकड़ों आवेदन भी तैयार कराए गए। कार्यक्रम में जितेन्द्र प्रसाद, साहबजान अंसारी, नेहा देवी, गीता देवी, रम्भा देवी, सुमन देवी, विश्वकला देवी, उमेश प्रसाद, सुभावती देवी, चैन पतिया देवी सहित बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक बनाना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना रहा।

महिला आयोग की सदस्या जनक नंदिनी ने परखी योजनाओं की जमीनी हकीकत, अस्पताल की अव्यवस्था पर जताई नाराजगी

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश राय महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी ने बुधवार को जनपद में महिला सशक्तिकरण एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का जायजा लेने के लिए विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा, महिला जनसुनवाई कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्र, वृद्धाश्रम तथा वन स्टॉप सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से सीधे संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मरीजों ने अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने की समस्या बताई, जिस पर सदस्या ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को तत्काल मशीन ठीक कराने तथा मरीजों का अल्ट्रासाउंड अस्पताल परिसर में ही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लेबर रूम, परिवार नियोजन परामर्श कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, पीकू वार्ड और दवा वितरण कक्ष का भी निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली तथा सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत पात्र मरीजों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके बाद तहसील सभागार हाटा में आयोजित जन चौपाल एवं महिला जनसुनवाई कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान कुल 23 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिन पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने और सात दिनों के भीतर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सदस्या ने कहा कि महिलाओं और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। दौरे के क्रम में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय हाटा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई तथा बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार सम्पन्न कराया गया।

निचलौल पूर्व चेयरमैन सहित चार घरों के अवैध पेयजल के काटे गए कनेक्शन

महराजगंज।

निचलौल नगर पंचायत प्रशासन ने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाने और सभी वार्डों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान पूर्व चेयरमैन समेत चार लोगों के घरों में अवैध पेयजल कनेक्शन पकड़े गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से काट दिया गया। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर पंचायत के अनुसार महराजगंज ठूठीबारी मार्ग के निर्माण कार्य के कारण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के समाधान और जल वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न वार्डों में जांच अभियान संचालित किया गया। लिपिक मोहन लाल की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय टीम ने कृष्णा नगर वार्ड सहित अन्य वार्डों में पेयजल कनेक्शनों का सत्यापन किया। जांच के दौरान पूर्व चेयरमैन

नगर में पेयजल कनेक्शन की जांच करते नगर पंचायत कर्मचारी

> **जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चलाया गया था विशेष अभियान, जांच में बिना कनेक्शन के ही घरों और दुकानों में हो रही थी पेयजल आपूर्ति, पूर्व सभासद के घर में भी बिना कनेक्शन के सालों से हो रही थी पेयजल आपूर्ति**

विश्वनाथ मद्धेशिया, पूर्व सभासद राकेश मद्धेशिया, संजय कुमार व नीरज कुमार के निजी आवासों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अवैध रूप से पेयजल कनेक्शन संचालित पाया गया। जांच समिति ने संबंधित उपभोक्ताओं से कनेक्शन से संबंधित अभिलेख और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन कोई भी आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं करा जा सका। इसके बाद नगर पंचायत की टीम ने प्लंबर के माध्यम से सभी अवैध कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से विछेदित कर दिया। नगर पंचायत प्रशासन ने बताया कि पेयजल व्यवस्था में अनियमितता और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जांच टीम ने पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट

तैयार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए निकाय प्रशासन को भेज दी है। अभियान में मोहन लाल, अवधेश कुमार, मोहम्मद अनस, पत्रेलाल, नितीश गुप्ता, मानवेंद्र यादव, अवध बिहारी पाण्डेय, शिवेन्द्र यादव व ह्रदेश उर्फ सोनू सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

गो-तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई- दो गो-तस्कर गिरफ्तार, दो गोवंशीय बछड़े व बोलेरो बरामद

कुशीनगर। जनपद में गोवंशीय पशुओं की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना पटहेरवा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने तस्करी कर वध के लिए ले जाए जा रहे दो गोवंशीय बछड़ों को बरामद करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक संशोधित बोलेरो वाहन, दो बांका, एक अवैध चाकू तथा एक लकड़ी का ठीहा भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बिहार के पश्चिमी चम्पारण जनपद के थाना धनहा क्षेत्र स्थित दहवा निवासी नबी हसन अंसारी पुत्र मुस्तफा तथा मखलूक अंसारी उर्फ भुट्ट पुत्र मुस्तफा के रूप में हुई है। दोनों को थाना पटहेरवा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना पटहेरवा में मु0अ0सं0 183/2026 के तहत गोवध अधिनियम की धारा 3/5/5ए/8, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इसी प्रकरण में 16 जून को भी दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो कुशीनगर-बिहार सीमा से सटे क्षेत्रों में घूमने वाले छुट्टा गोवंशीय पशुओं को चोरी कर रात के समय बिहार ले जाता है। वहां पशुओं का वध कर मांस बेचने के बाद प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली जाती है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार नबी हसन अंसारी के विरुद्ध पूर्व में भी गोवध एवं संबंधित धाराओं में दो मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मखलूक अंसारी उर्फ भुट्ट के खिलाफ वर्ष 2025 में गोवध अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। बरामद सामान में दो गोवंशीय बछड़े, एक संशोधित बोलेरो वाहन (यूपी57D0090), एक लकड़ी का ठीहा, दो बांका तथा एक अवैध चाकू शामिल है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष धीरेन्द्र राय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा की गई, जिसमें उपनिरीक्षक श्रवण कुमार, रामप्रवेश सिंह, अनुराग यादव, सच्चिदानंद यादव तथा अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

देवरिया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक - मेडिकल कॉलेज में योग कक्ष का शुभारंभ, विकास भवन में प्रदर्शनी का उद्घाटन

देवरिया।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को जनपद के अपने एक दिवसीय आधिकारिक भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी समीक्षा की। उन्होंने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राय चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर परिसर में वृक्षारोपण किया और नवनिर्मित योग कक्ष का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इसके तत्काल बाद उप मुख्यमंत्री ने विकास भवन परिसर पहुंचकर केंद्र सरकार के कार्यकाल पर आधारित 12 साल विश्वास, विकास एवं जनकल्याण विषयक दो दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मेडिकल कॉलेज के सफल संचालन को लेकर उप मुख्यमंत्री ने प्राचार्य व वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने संस्थान की स्वायत्तता को मजबूती देते हुए विधिक निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज की फैकल्टियों में रिक्त चल रहे पदों को तत्काल भरने का अधिकार अब सीधे प्राचार्य के पास होगा, शासन स्तर से केवल इस चयन प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता की निगरानी की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध वित्तीय कोष का नियमानुसार समुचित उपयोग किया जाए, आवश्यकता पड़ने पर सरकार अतिरिक्त बजटीय सहायता भी देगी। इसके अलावा उन्होंने सीसीटीवी नेटवर्क को चौबीस घंटे सक्रिय रखने, छात्रावासों में छात्र-छात्राओं

> **डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी में रिक्त पद भरने के लिए प्राचार्य को दिए अधिकार**
> **रोगी कल्याण समिति के बजट का सही उपयोग करने की हिदायत, विकास भवन में बच्चों का कराया अन्नप्राशन**

की सहूलियतें बढ़ाने और परिसर के अधूरे भवनों में फिनिशिंग व रंगाई-पुताई का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

भ्रमण के अगले चरण में डिप्टी सीएम ने विकास भवन में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने वहां विभिन्न राजकीय विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों की प्रगति जांची। इस दौरान आईसीडीएस विभाग के स्टॉल पर उन्होंने नौनिहालों का अन्नप्राशन कराया तथा 5 दिव्यांग लाभार्थियों को आत्मनिर्भरता के लिए ट्राइसाइकिल वितरित की। बेसिक शिक्षा विभाग की छात्राओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और ओडीओपी के स्थानीय उत्पादों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी आम जनता को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का एक प्रभावी प्रशासनिक माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन की ओर से अतिथियों को महर्षि देवराहा बाबा का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

आखिरकार टूट गया हनक और रसूख का अहंकार, 4 महीने बाद दिल्ली से दबोची गई 25 हजार की इनामी बीएसए शालिनी श्रीवास्तव

देवरिया ।

(गौरव कुशवाहा) शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह को आत्महत्या के दलदल में धकेलने वाली भ्रष्टाचार के सिंडिकेट की मुख्य सूत्रधार और निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव की फरारी का अंत हो गया है। पिछले चार महीनों से कानून की आंखों में धूल झोंककर भाग रहीं 25 हजार रुपये की इनामी शालिनी श्रीवास्तव को गुलरिहा पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी साक्ष्यों, सर्विलांस और सटीक मुखबिरी के जाल में फंसीं साहिबा का रसूख आखिरकार खाकी के इकबाल के आगे ढेर हो गया। पुलिस गहन पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय के कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी होने और एसएसपी डॉ. कौस्तुभ द्वारा इनाम की राशि 25 हजार किए जाने के बाद से ही पुलिस शालिनी को मोस्ट वांटेड अपराधी की तरह तलाश रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शालिनी लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थीं, लेकिन दिल्ली में उनके छिपे होने के तकनीकी इनपुट मिलते ही गुलरिहा पुलिस की विशेष टीम ने दबिश देकर उन्हें दबोच लिया। हालांकि, इस पूरे

सिंडिकेट का वसूलीबाज बाबू संजीव सिंह अभी भी फरार

> निलंबित बीएसए को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। निलंबित लिपिक संजीव सिंह की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही वह भी पुलिस की गिरफ्त में होगा।
> — निमिष पाटील, एसपी सिटी, गोरखपुर।

खूनी सिंडिकेट का दूसरा मुख्य मोहरा निलंबित लिपिक संजीव सिंह अब भी पुलिस को चुनौती देते हुए फरार है। प्रकरण की शुरुआत 21 फरवरी 2026 को हुई थी, जब कुशीनगर के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह ने प्रताड़ना से तंग आकर अपने भाई के मकान में फंदा लगा लिया था। अगले दिन उनकी पत्नी गुड़िया सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। जांच में सामने आया कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के नाम पर कृष्ण मोहन, ओमकार और अपर्णा तिवारी से 16-16 लाख रुपये (कुल 48 लाख) की अवैध वसूली की गई थी। शिक्षकों ने अपने गहने गिरवी रखकर और कर्ज लेकर यह रकम चुकाई थी, लेकिन 20 फरवरी को बीएसए कार्यालय में बुलाकर उन्हें जिस तरह अपमानित और प्रताड़ित किया गया, उसने एक शिक्षक की जान ले ली। मृतक शिक्षक की जेब से बरामद चार पन्नों का सुसाइड नोट और वीडियो संदेश इस केस में शालिनी श्रीवास्तव की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने घटना के ठीक 10 दिन बाद, डील कराने वाले पूर्व प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसने सिंडिकेट के कई राज उगले थे।

45 दिन में दिल्ली की पांच झुग्गी बस्तियों का बदलेगा नक्शा, पक्के घर की ओर बढ़ेंगे लाखों परिवार

नई दिल्ली। दिल्ली की झुग्गी और जेजे क्लस्टर बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए पक्के घर का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में 'दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' को मंजूरी मिलने के बाद अब इसके क्रियान्वयन की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में अगले 45 दिनों के भीतर पांच जेजे क्लस्टरों के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई इस मीटिंग में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह विभाग मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बताया कि नीति को जमीन पर उतारने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और डूसिब जल्द ही पांच जेजे क्लस्टरों के लिए व्यावसायिक टेंडर जारी करेंगे। इसके बाद हर महीने कम से कम पांच ऐसी परियोजनाओं के टेंडर निकालने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पुनर्वास प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को बेहतर और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्षों से अस्थायी परिस्थितियों में रह रहे लोगों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्थायी घर मिल सकें। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि दिल्ली के शहरी विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

सिर्फ मकान नहीं, पूरी सुविधा वाला आवासीय विकास

पुनर्वास परियोजनाओं में केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहा जाएगा। नए क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी और अन्य जरूरी सामाजिक सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे पुनर्वासित परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सेवाएं उनके नए आवास के आसपास ही उपलब्ध हो सकेंगी।

'जहां झुग्गी वहां मकान' योजना को मिलेगी गति

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'जहां झुग्गी वहां मकान' पहल के तहत दिल्ली की अनधिकृत झुग्गी बस्तियों को व्यवस्थित आवासीय क्षेत्रों में बदलने की योजना बनाई गई है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने इसे राजधानी को विकसित भारत के अनुरूप विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि नीति लागू होने से लाखों परिवारों को सम्मानजनक आवास, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा। प्रशासन का मानना है कि झुग्गी पुनर्वास नीति से दिल्ली में अनियोजित बस्तियों की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। योजनाबद्ध विकास के जरिए जहां जरूरतमंद परिवारों को बेहतर जीवन मिलेगा, वहीं राजधानी में आधुनिक और समावेशी शहरी ढांचे को भी बढ़ावा मिलेगा।

उद्धव की पार्टी टूटी, राउत ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में गाली दी

9 में से 6 सांसद बागी; 4 साल पहले शिंदे 39 विधायकों के साथ अलग हुए थे

- बागी सांसदों पर भड़के संजय राउत- खुलेआम दी भद्दी-भद्दी गालियां, मीडिया से कहा कि वे उनके कमेंट्स को न काटें
- चार्टर्ड फ्लाइट और 15 करोड़ का दावा- 2022 दोहराया तो चुप नहीं बैठेंगे, टूट की अटकलों पर राउत ने दी चेतावनी

मुंबई । महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट की अटकलों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरे पास जानकारी है कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इसके बाद वे नांदेड़ और पुणे सहित तीन जगहों से चार्टर्ड फ्लाइट में सवार हुए। हमने कल होने वाली संसदीय दल की बैठक के लिए व्हिप जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी सांसद अरविंद सावंत ने इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। शिवसेना (यूबीटी) के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से केवल तीन सांसद, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और अरविंद सावंत ही संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। बाकी सांसदों की अनुपस्थिति ने पार्टी में संभावित बगावत और टूट की चर्चाओं को और हवा दे दी है। संजय राउत ने कहा कि अगर 2022 की तरह एक बार फिर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई तो महाराष्ट्र की जनता और शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टियों को तोड़कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। यदि राजनीतिक दलों को इस तरह तोड़ा जाएगा तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

बागी सांसदों को दिया इस्तीफे का सुझाव

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व का बचाव करते हुए राउत ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कड़ी मेहनत कर सांसदों को चुनाव जिताया है। उन्होंने संभावित बागी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी को पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ जाना है तो पहले सांसद पद से इस्तीफा दें और फिर जनता के बीच जाकर जनादेश लें।

हाईवे पर रेस लगा रहे ट्रैक्टरों ने ई-रिक्शा को रौंदा, छह महिलाओं की मौत, तीन घायल

बदायूं । बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र में बुधवार दोपहर भीषण हादसा हो गया। दो ट्रैक्टर चालकों की लापरवाही से छह महिलाओं की मौत हो गई। तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद एक चालक अपना ट्रैक्टर और ट्रॉली दौड़ा ले गया, जबकि दूसरा चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसके ट्रैक्टर और ट्रॉली को कब्जे में लिया है। दोनों चालकों की तलाश शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक कछला और उझानी के बीच फूलपुर क्षेत्र में बुधवार दोपहर हाईवे पर दो ट्रैक्टर चालक रेस लगा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रैक्टरों ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार महिलाएं व अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग जुट गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां छह महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में रिक्शा चालक सनी (32 वर्ष), छत्र सिंह (58 वर्ष) समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कछला के मोहल्ला मुगवन नगला निवासी छत्र सिंह के बेटे कुंवर पाल की शादी 29 जून को होनी है। परिवार की महिलाएं शादी की रस्म भात मांगने के लिए पड़ोसी पठोना गांव जा रहे थे। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। परिवार में कोहराम मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही गांव के लोग और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। चीख-पुकार मच गई।

भगवंत मान पर गहराया नैतिक संकट, बीजेपी ने की इस्तीफे की मांग तेज

पंजाब । बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने बुधवार को कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। यह बात सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था, श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा एक विवादित वीडियो पर दिए गए फैसले के बाद कही गई है। इस वीडियो में कथित तौर पर सिख धर्म की सम्मानित हस्तियों और भावनाओं का अनादर किया गया है। चुघ ने याद दिलाया कि जब कई महीने पहले यह वीडियो पहली बार सामने आया था, तो मान ने इसे बनावटी बताते हुए खारिज कर दिया था और दावा किया था कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। वह श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के सामने पेश हुए और चुनौती दी कि किसी सक्षम एजेंसी से इस वीडियो की जांच कराई जाए, क्योंकि यह नकली है। चुघ के अनुसार, इस तरह मान ने अपनी विश्वसनीयता को उस जांच के नतीजे पर टिका दिया था। 15 जून को पंथिक हस्तियों, संस्थाओं और सिख संगठनों के साथ हुई बातचीत में सारी सच्चाई सामने आ गई। चुघ ने कहा कि वीडियो को देश की दो मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, और दोनों ने बिना किसी संदेह के यह निष्कर्ष निकाला कि वीडियो असली था, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी और वह हू-ब-हू से नहीं बनाया गया था। जिस टेस्ट के लिए भगवंत मान ने खुद कहा था, वही आज उनके अपने ही आचरण के खिलाफ एक आरोप बन गया है। इन नतीजों के आधार पर, सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने भगवंत मान को गुरु-द्रोही और पंथ-विरोधी करार दिया और सिख संगत को उनका सामाजिक बहिष्कार करने की सलाह दी। इस अभूतपूर्व निंदा ने दुनिया भर में नानक नाम लेवा संगत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और एक ऐसी नैतिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी है जिसका सामना पहले किसी मुख्यमंत्री को नहीं करना पड़ा था।

टेलीग्राम भारत में बेन: मोदी जी, ड्रामा छोड़िए! राहुल बोले- माफिया पर वार करें, छात्रों पर नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नीट-यूजी पेपर लीक की चिंताओं के बीच टेलीग्राम पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय छात्रों को निशाना बना रही है। यह कदम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा मंगलवार को भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर एक तय और सीमित समय के लिए रोक लगाने के बाद उठाया गया है। यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी, जिसमें नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा का दिन और उसके ठीक बाद का समय भी शामिल है। एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने कहा कि टेलीग्राम पर बैन- पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार का नया हथकंडा। यानी, चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के दरवाज़े पर ही ताला लगा दो। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर लीक की समस्या का समाधान इस सुविधा को छीनना नहीं है। पोस्ट में लिखा था कि लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ाई कर रहे हैं - नोट्स, टेस्ट सीरीज़, चर्चा और तैयारी। तो फिर, उस सुविधा को छीनना पेपर लीक का समाधान कैसे हो सकता है ऐसे कदमों की असरदारता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा कि और यह तरीका पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है - देश का हर छात्र यह बात जानता है, और पेपर लीक करने वाला माफिया भी। तो, अगला बैन किस पर लगेगा व्हाट्सएप पर परीक्षा के दिन की व्यवस्थाओं पर तंज कसते हुए गांधी ने कहा कि परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी ली जाएगी। कैंची से जेबें काटी जाएंगी। प्रश्न पत्र एयर फोर्स के ज़रिए भेजे जाएंगे। ड्रामेबाज़ी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन समस्या की जड़ पर कोई प्रहार नहीं होगा - क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की नाक के नीचे फल-फूल रहा है और युवाओं को खून के आँसू रुला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी - ड्रामेबाज़ी छोड़िए। माफ़िया पर प्रहार कीजिए, छात्रों पर नहीं। छात्रों को आवाज़ सुनिए - वरना देश के युवा जानते हैं कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। यह बयान तब आया है जब केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुरोध पर टेलीग्राम को ब्लॉक करने का आदेश दिया। एनटीए ने आरोप लगाया था कि संगठित नकल गिरोह इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल 21 जून को होने वाली नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को गुमराह करने और उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए कर रहे थे।

ईरान के साथ एमओयू फाइनल नहीं, अगर पसंद नहीं आया तो हम फिर करेंगे अटैक- डोनाल्ड ट्रंप

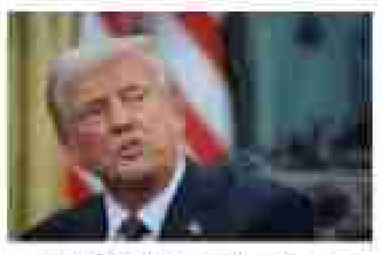

समझौते की सुगबुगाहट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया. फ्रांस में चल रहे जी7 समिट के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के साथ अभी एमओयू फाइनल नहीं है. ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमले की भी धमकी दे डाली. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल जी7 समिट में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे हैं. समिट के दौरान उन्होंने ईरान के साथ समझौते पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हमने ईरान में सब कुछ नष्ट कर दिया है. ईरान के साथ डील अभी फाइनल नहीं है. ट्रंप यहां तक नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो हम फिर से हमला करेंगे.

फैजल खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर अड़े रौशन आनंद, समर्थकों संग थाने के बाहर धरने पर बैठे

पटना । ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद अपने भाई प्रिंस यादव की मौत के मामले में चर्चित शिक्षक फैजल खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कदमकुआं थाने पहुंचे। पुलिस द्वारा मामला दर्ज न किए जाने से नाराज रौशन आनंद बड़ी संख्या में छात्रों और समर्थकों के साथ थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। रौशन आनंद बुधवार को कदमकुआं थाना पहुंचे और थानाध्यक्ष जन्मेजय राय को लिखित आवेदन दिया। उनका आरोप है कि उनके भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के पीछे फैजल खान की भूमिका है। जब पुलिस ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया, तो रौशन आनंद थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में आए छात्रों की भारी भीड़ पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही है। पिछले कई घंटों से यह गतिरोध जारी है और रौशन आनंद के वकील भी मौके पर पहुंच चुके हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, धरना समाप्त नहीं होगा।

कोर्ट से फिर लगा झटका

एक तरफ जहां रौशन आनंद थाने के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ अदालत से रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। कोचिंग विवाद से जुड़े एक पुराने मामले में जेल में बंद रौशन आनंद के भाई अभिषेक और उनके सहकर्मी गौरव की जमानत याचिका को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अब गुरुवार को आदेश की प्रति निकालकर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दोबारा जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। थाना पहुंचने से ठीक पहले रौशन आनंद इस पूरे मामले को लेकर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय झा से मुलाकात की थी। उन्होंने अपने भाई की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई। मुलाकात के बाद संजय झा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरे प्रकरण की पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी।

खरगे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला; समिति करेगी जांच

नई दिल्ली । राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के छह सांसदों ने मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। भाजपा सांसदों का आरोप है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के बारे में सदन में अपमानजनक और असम्मानजनक टिप्पणी की, जिससे सदन की गरिमा और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन हुआ है। इसी आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया गया। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस नोटिस पर संज्ञान लेते हुए इसे आगे की जांच और परीक्षण के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। समिति मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंपेगी। अब विशेषाधिकार समिति यह तय करेगी कि मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करती है या नहीं। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस घटनाक्रम से संसद के मानसून सत्र से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। यह नोटिस भाजपा के छह राज्यसभा सांसदों; बृज लाल, मिथलेश कुमार, सुमित्रा बाल्मिक, शिवेश कुमार, सिकंदर कुमार और नागेंद्र राय; ने संयुक्त रूप से दिया है। सांसदों का कहना है कि खरगे लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो संसद की मर्यादा के खिलाफ है।

किस नियम के तहत दिया गया नोटिस?

यह नोटिस राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 188 के तहत दायर किया गया है। इसके बाद सभापति ने नियम 203 के तहत मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। अब विशेषाधिकार समिति इस मामले की जांच करेगी, संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्यसभा को सौंपेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

विशेषाधिकार समिति में कौन-कौन हैं?

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, दीपक प्रकाश, सुमेर सिंह सोलंकी, सुरेंद्र सिंह नागर, मनन कुमार मिश्रा तथा निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा सदस्य हैं।

ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उठाया भारतीय नाविकों का मुद्दा

नई दिल्ली/एवियन (फ्रांस) । फ्रांस में चल रहे जी7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट भारतीय जहाजों पर हुए हमले पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में स्थाई शांति होनी चाहिए. मिडिल ईस्ट में जो समझौता हो रहा है उसमें भारतीय नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहा, हमने हमेशा कहा है कि समुद्र में आवाजाही की आजादी पक्की होनी चाहिए और हमें इस बात पर जोर भी देना चाहिए. समुद्री व्यापार के क्षेत्र में दुनिया के अलग-अलग समुद्रों में लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं. मेरा मानना है कि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. मुझे भरोसा है कि (ईरान के साथ) समझौते में नाविकों की सुरक्षा पक्की की जाएगी और उसे प्राथमिकता दी जाएगी.

पीएम मोदी मेरे लंबे वक्त से मेरे दोस्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फ्रांस में हमारी कुछ बहुत अच्छी बैठकें हुई. यह जी7 है. इसके बाद जी2 और फिर जी20 होने वाली है. खास तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई. हम व्यापार समझौते कर रहे हैं. अमेरिका और भारत के बीच बहुत कुछ हो रहा है. अमेरिका अब तक के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है. हमारे पास 19.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा आ रहे हैं और हम फैक्टरियां बना रहे हैं, हम सब कुछ बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका में बहुत कुछ बना रहे हैं. वह अमेरिका में काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए हम उनके इस काम की सराहना करते हैं. लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वह लंबे समय से मेरे दोस्त रहे हैं, और हमारे रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और आपके साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है.

मोदी कूल और टफ वार्ताकार

द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि मोदी एक टफ वार्ताकार हैं, मैं जल्द भारत जाऊंगा, जब तक मोदी हैं भारत की भूमिका अहम है, पीएम मोदी से हमारे रिश्ते अच्छे हैं. भारत में मोदी के लिए बहुत सम्मान है, मेरे कार्यकाल में भारत से अच्छे संबंध हैं, मोदी कूल हैं लेकिन टफ हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, उन्हें (भारत को) व्हाइट हाउस में एक बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा. वहां हर कोई भारत को पसंद करता है और वे इस पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं. पीएम मोदी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह बातचीत में बहुत सख्त हैं. आप इस व्यक्ति (पीएम मोदी) को देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं. वह दिखने में बहुत अच्छे हैं. वह बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कोई फरिश्ता हो. लेकिन असल में, वह उतने ही सख्त हैं. लेकिन वह बहुत अच्छे दिखते हैं. इसलिए वह आपको चौंका देते हैं. लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं. लोग कहते हैं कि वह बहुत अच्छे इंसान हैं. वह भारतीय लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन वह अमेरिका से भी प्यार करते हैं. हमने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था. स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था. हम भविष्य में कभी भारत जाएंगे.

मेरा पिछला भारत का दौरा शानदार रहा था- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पिछली बार भारत का मेरा दौरा बहुत शानदार रहा था. हमने उस नए स्टेडियम का उद्घाटन किया था, और मुझे लगता है कि वहां 3000-4000 लोग थे. स्टेडियम में लगभग 150,000 लोगों के बैठने की जगह थी, और बाहर 250,000 लोग थे, और 100,000 लोग घास पर बैठे थे. मुझे नहीं पता कि वे रिकॉर्ड टूटे हैं या नहीं. लेकिन भारत में मेरा समय बहुत अच्छा बीता. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि भारत पश्चिम एशिया में कोई भूमिका निभाएगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हां, मुझे उम्मीद है. मुझे लगता है कि भारत हर चीज में बड़ी भूमिका निभाता है. जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भारत बड़ी भूमिका निभाता रहेगा.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर क्या बोले ट्रंप?

रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन से बात की. हम चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो. मैंने 8 युद्ध खत्म किए हैं और सच कहूं तो, यह सबसे आसान युद्धों में से एक हो सकता था, लेकिन वे एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, जिससे यह और मुश्किल हो जाता है.